Study of Indian Banking System

2795, SHRI GHUFRAN AZAM:

DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem captioned "Indian banking system unviable" as reported in the Economic Times of the 20th July, 1992;

(b) if so, whether ths World Bank and RBI have jointly conducting a study on the Indian banking system and found that there is deterioration in the quality of banking system; and

(c) if so, what are the details of the study report and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Chambers of Commerce and Industry's suggestion on Taxation

2796. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several Chambers of Commerce and Industry in the country have advocated single point. single-tax and single authority system, instead of the present arrangements; and

(b) if so, what is the reaction of Government to these suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Representations had been received from Trade Industry, and Chambers of Commerce for introduction of single-point sales tax. Sales tax is a State subject and it is an important source of revenue for the States. It is for the States to take up and decide the changes, if any, repaired in their respective Sales Tax and other State tax laws.

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने का मानदंड

2797. श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की शाखायें खोलने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या पहाड़ी, पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कुछ शर्तों/नियमों में छूट दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) चूंकि वर्ष 1985–90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति में ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक कार्यालय के अंतर्गत आने वाली 17,000 की औसत जनसंख्या के लक्ष्य की तुलना में, अब यह औसत कम हो कर 12,000 हो गया है अत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्षों की भांति किसी भी खास अवधि के लिए जनसंख्या कवरेज जैसे लक्ष्यों सहित कोई भी शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भावी शाखा विस्तार संबंधी दृष्टिकोण अब निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सुस्थापित आवश्यकताओं, कारोबार क्षमता और प्रस्तावित कार्यालय की वित्तीय अर्थक्षमता पर आधारित है।

(i) किसी बैंक शाखा को आवंटित किया गया सेवा क्षेत्र, अधिक संख्या में आवंटित किए गए गांवों, प्रदान किए जाने वाले संघटकों की संख्या और किसी क्षेत्र में सेवायें प्रदान करने में अंतर्ग्रस्त अधिक